WITWAVES
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
Vol-2 Issue-2
(International Peer-Reviewed E-Journal)
(February 2025)

बागवानी खेती: अनुसंधान, विकास एवं बढ़ती आमदनी

संतोष कुमार रावत
सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)

शोध पत्र सारांश

यह शोध पत्र भारत में बागवानी फसलो के असनुसंधान, उत्पादन, किसानों की आय व उनकी आमदनी, खुशहाली, में वृद्धि का अध्ययन करता है। भरतीय कृषि में बागवानी के महत्व को नकारा नही जा सकता है, इस क्षेत्र से कुल कृषि उत्पादन के मूल्य का 30-33 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है, बेहतर उत्पादकता वर्ष 2023-24 में भारत का बागवानी उत्पादन प्रतिवर्ष 1.37 प्रतिशत बढकर 351.92 मिलियन टन हो गया है। किसान अलग-अलग बागवानी फसलें उगाकर खासी अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे है। आमदनी में वृद्धि से किसानों के जीवन मे निश्चित रुप से खुशहाली देखने को मिली है, बागवानी फसलों पर किये जा रहे व्यापक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरुप इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई है। प्रमुख उपलब्धियां इन फसलों की नई बेहतरीन किस्मों के विकास के क्षेत्र में है। फलों में तमाम उन्नत किस्मे पहचानी गई है, जिनमें कम खर्च व कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है। किन्तु कुछ चुनौतियां भी इस क्षेत्र में है, जिन्हें इस शोध पत्र में चिन्हित किया गया है।

मुख्य शब्द

खुशहाली, आमदनी, वृद्धि, अनुसंधान, उत्पादन आदि।

बागवानी कृषि से मानव इतिहास उतना ही पुराना है, जितनी की मानव सभ्यता मानव पुरातन काल से ही बागवानी फसलों को किसी न किसी रुप में अपनी आवश्यकता अनुसार करता आ रहा है, फल, फूल, सजावटी पौधे उगाने की कला और विज्ञान ही बागवानी के नाम से जानी जाती थी,बागवानी किसी न किसी रूप में महाभारत व रामायण काल मे भी देखने को

मिलती है, आम तौर पर बागवानी की शुरुआत लगभग 10000 से 20000 वर्ष पूर्व मानी जाती है, यह भारत मे ही नही बल्कि विश्व के सभी देशो में देखने को मिलती है, किन्तु भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस लिये भारतीय कृषि में बागवानी का महत्व और बढ जाता है। इससे कुल कृषि उत्पादन मूल्य का 30 से 33 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। बागवानी फसलों के अर्न्तगत 1 करोड 36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आता है, जो कुल कृषि भूमि का 7 प्रतिशत है, जब देश आजाद हुआ था तब सबसे ज्यादा ध्यान कृषि क्षेत्र पर दिया गया यानी अन्न के उत्पादन पर 1960 के दशक में कृषि में हरित क्रन्ति आने से देश में खाद्यान उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। जो हरित क्रान्ति अवधि 1968 से 1988 तक वास्तव में देखी गई, अनाज की दैनिक उपलब्धता जो सन् 1950 में 350 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी, वह बढकर 1989-90 में 600 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई, इससे खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भता के युग की शुरुआत हुई,दूसरी ओर भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में गेहूँ एवं धान पर आधारित भू-उपयोग प्राणाली की प्रधानता एवं सघन फसल पद्धति अपनाने के कारण जलपट्टी स्तरो के नीचे खिसकने से, मिट्टी के उर्वरता में भारी गिरावट, आने और कीट व्याधियों के व्यापक रूप में प्रकट होने जैसी अनेक समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ नतीजा यह हुआ कि साल-दर-साल सरकार द्वारा भारी साब्सिडी देने और निर्धारित कीमतों पर अनाज खरीदने के बावजूद शुद्ध आमदनी में गिरावट आने के स्पष्ट संकेत मिलने लगे।

अत: उत्पादन में आधुनिक तकनीक अपनाकर इन फसलों की नई किस्मों की अनुवांशिकी उत्पादन क्षमता का पूर्ण दोहन करके देश में ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित आर्थिक बदलाव लाया जा सकता है। इन फसलों के उत्पादन पर धान्य फसलों के मुकाबले कम खर्च आता है। और 30 से 35 प्रतिशत अधिक आय प्राप्त होती है। फलों एवं सब्जियों की घरेलू खपत की वार्षिक वृद्धि दर सन् 1990-91 में 3.5 प्रतिशत थी, जो बढ़कर वर्तमान में 2024-25 में 12.5 प्रतिशत तक आ गई है। इस संकेत के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि देश में सन् 2030 तक फलों एवं सब्जियों की मांग बढ़कर क्रमश: 15.5 एवं 21 करोड़ टन को पार कर जायेगी इससे उन दबावों को संकेत मिलता है जो हम पर फलों एवं सब्जियों के उत्पादन बढ़ाने के लिए पड़ सकते हैं। जैसे-जैसे लोग बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगे, ये दबाव और भी बढ़ते जायेंगे क्योंकि लोगों का मानना है कि यदि व्यक्तियों को स्वास्थ्य रहना है व बिमारियों से

लड़ना है तो फलों एवं सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना होगा, इस बात को ध्यान में रखकर उत्पादन बढ़ाना ही होगा।

विकास कार्यक्रम

चौथी पंचवर्षीय योजना कल तक गेहूं एवं धान पर आधारित भू-उपयोग प्रणाली की प्रधानता के कारण बागवानी विकास पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया कारण स्पष्ट था कि देश में खाद्यान्न की भारी कमी थी परिणाम यह हुआ कि इस क्षेत्र में अनुसंधान विस्तार और उत्पादन की बुनियादी सुविधाओं का विकास काफी प्रतिबंधित रहा और हम बागवानी क्षेत्र में बिछड़ते चले गए पांचवी छठवीं और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में बागवानी विकास पर क्रमशः 7.60 9.13 एवं 24 करोड रुपए खर्च किए गए थे, आठवीं योजना (1992-97) में भारतीय कृषि को निर्यातोंमुखी बनाने, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था सुधारने में बागवानी के महत्व को स्वीकारते हुए बागवानी विकास को प्राथमिकता दी गई थी, आठवीं योजना को भारतीय बागवानी विकास की दृष्टि से मील का पत्थर कहा जा सकता है। जिसमें 1000 करोड रुपये का रिकॉर्ड आवंटन बागवानी के लिए किया गया था, आठवीं योजना में फलों के विकास हेतु 85 करोड रुपये की राशि निर्धारित की गई थी, जबकि सातवीं योजना में इस मद पर मात्र 3.58 करोड रुपए खर्च किए गए थे, किसानों को उन्नत किस्म के रोग रहित फल वाले पौधे उपलब्ध न होने की समस्या को सरकार ने गंभीरता से लिया था, इसके लिए इस योजना में राज्य सरकारों के अधीन 85 बड़ी और निजी क्षेत्र में 350 छोटी पौधशालाये स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था जिन पर क्रमश: 1530 एवं 70 लाख रुपए खर्च किए जाने की व्यवस्था की गई थी इसके अलावा निजी क्षेत्र में 20 और सरकारी क्षेत्र में 17 ऊतक संवर्धन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए क्रमशः 200 एवं 357 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे।

बागवानी फसलों की खेती में प्लास्टिक के उपयोग पर पहली बार बल दिया गया था, इसके लिए 25 करोड रुपए खर्च किए जाने की व्यवस्था की गई थी, प्लास्टिक उपयोग में ड्रिप सिंचाई मल्चिंग एवं ग्रीन हाउसों का निर्माण शामिल था, आठवीं योजना के अंत तक 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ट्रिप्स सिंचाई तकनीकी अपने का लक्ष्य रखा गया था एक हेक्टेयर क्षेत्र में डिप

सिंचाई की अनुमानित लागत 30 हजार रू आती है जिसके लिए 50 प्रतिशत की छूट पर किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी, भूमि में अधिक समय तक नमी बनाए रखने, खरपतवारों द्वारा होने वाले नुकसान को रोकने तथा रोक मुक्त फसलें पैदा करने के उद्देश्य से 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्लास्टिक मल्च द्वारा बागवानी फैसले उगाने का लक्ष्य रखा गया था, इसके लिए प्लास्टिक सीट की खरीद पर किसानों को 50 प्रतिशत की छूट देने की व्यवस्था की गई थी वायुमंडलीय तापमान एवं सापेक्षिक आद्रता को नियंत्रित कर बेमौसमी फसले उगानें के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में 500 वर्ग मीटर आकार के 11500 ग्रीन हाउस बनाने का लक्ष्य रखा गया था, कम मध्यम तथा अधिक लागत वाले ग्रीन हाउसों कि निर्माण के लिये क्रमश: 50, 40 एवं 10 प्रतिशत की छूट देने का प्रविधान किया गया था। सन् 1988 में जो राष्ट्रीय बीज नीति बनाई गई थी उसके अन्तर्गत उन्नत किस्मों के बीज एवं पौध रोपण समाग्री के आयात को खुली छूट दे दी गई थी, बागवानी से सम्बंधित वस्तुओं के आयात पर शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था, फल एवं सब्जियें से निर्मित प्रसंस्करित उत्पादों पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया था।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में प्रयुक्त समंको का अध्ययन करने से यह स्पस्ट हो गया है, कि देश में आजादी के बाद बागवानी फसलों में काफी अनुसंधान हुए है, एवं यह कृषको के लिए कम समय में अतिरिक्त आय कमाने का बेहतरीन जरिया है, क्योकि दिनों दिन बढती जनसंख्या की जरुरतों को पूरा करने हेतु प्रति वर्ष बागवानी फसलों, के अन्तर्गत फलों व सब्जियों की मांग, अत्यधिक बढती जा रही है, गांव देहात में ज्यादातर कृषको के पास कम भूमि होती है, जिसमें खद्यान्न फसलों को उगाने में असुबिधा होती है, किन्तु बागवानी फसलों में सब्जियों आदि को उगाने के लिए ज्यादा भूमि की भी आवश्यकता नही पडती है, और कम समय में फसल तैयार हो जाती है, जिसको बाजार में बेचकर किसान अपने परिवार व अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। आमदनी में वृद्धि से किसानों के जीवन मे निश्चित रुप से खुशहाली देखने को मिली है, बागवानी फसलों पर किये जा रहे व्यापक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरुप इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई है। प्रमुख उपलब्धियं इन फसलों की नई

बेहतरीन किस्मों के विकास के क्षेत्र में है। फलों में तमाम उन्नत किस्मे पहचानी गई है, जिनमें कम खर्च व कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. डॉ. सिंह एस.पी. आर्थिक विकास एवं नियोजन (भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में) एस. चन्द्र एंड कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली।
2. आर. ए. दुबे आर्थिक विकास एवं नियोजन नेशनल पब्लिशर्स हाउस नई दिल्ली 2006
3. एस. के. मिश्रा बी. के. पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस दिल्ली 2018.
4. अग्रवाल ए. एन. भारतीय अर्थव्यवस्था विकास पब्लिकेशन हाउस प्रा. लि. दिल्ली 2008
5. सिंह बी. राजेन्द्र ग्रामों का आर्थिक पुनरूधार साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 2008
6. दत्त सुन्दरम भारतीय अर्थव्यवस्था एस. चन्द्र पब्लिकेशन दिल्ली।
7. डॉ. शर्मा, डॉ. रामरतन भारतीय अर्थव्यवस्था म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल 2024
8. डॉ. चतुर्भुज भारत की आर्थिक समस्याएं साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 2017.
9. सिन्हा डॉ. वी. सी. एवं सिन्हा डॉ. पुष्पा अर्थव्यवस्था एस.बी.पी.डी पब्लिशिंग हाउस आगरा।
10. मोदी डॉ. अनिता किसान हित के लिए प्रतिबद्ध बजट कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार अप्रैल 2019